

# जीने लायक शहरों के लिए संतुलित विकास जरूरी

बुनियादी सुविधाएं हों तो भारतीय पेशेवरों को विदेश जाने की जरूरत नहीं

शहरों के साथ आसपास के इलाकों को भी विकसित करने की आवश्यकता

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर. नीति आयोग में कार्यक्रम निदेशक अन्ना रॉय ने कहा कि भारत के शहरों को रहने योग्य बनाने के लिए सिर्फ शहरों पर नहीं बल्कि उनके आसपास के इलाकों के विकास पर भी समान ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित रियल एस्टेट सम्मेलन में कहा कि अगर आसपास की बुनियादी सुविधाएं विकसित हों तो भारतीय पेशेवरों को विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. नीति आयोग में कार्यक्रम निदेशक अन्ना रॉय ने



शुक्रवार को कहा कि भारतीय शहरों को जीने लायक बनाने के लिए शहरों के साथ आसपास के इलाकों को भी विकसित करने की जरूरत है.

रॉय ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ के (सीआईआई) द्वारा

उन्होंने कहा कि किसी शहर में रहने के लिए कैसे सुविधाएं हैं और आसपास कैसा माहौल है यह भी मायने रखता है. उन्होंने कहा कि शहरों को विकसित करते समय यह जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे जीने लायक हों.

शहरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने और जीने लायक बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के शीर्ष 100 शहरों में एक भी भारतीय शहर न होने का यही कारण है. सिर्फ शहरों की प्रशासनिक सीमा तक ही नहीं आसपास के इलाकों को भी उसी तरह से तैयार किये जाने की जरूरत है. इस मौके पर देश में वाणिज्यिक रियल एस्टेट की स्थिति पर एक रिपोर्ट भी जारी की गयी.

रिपोर्ट के अनुसार, रियल एस्टेट में सबसे नया उभरने वाला वर्ग डाटा सेंटर तेजी से बढ़ रहा है. तेजी से बढ़ते 5जी नेटवर्क, एआई, वलाउड कंप्यूटिंग और डाटा को देश में ही स्टोर करने के आदेश के कारण भारतीय डाटा सेंटर बाजार 10 गीगावाट को पार कर चुका है जिसमें 1.4 गीगावाट सक्रिय हो चुका है. सीआईआई और नाइट फ्रैंकफर्ट इंडिया द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2000 से 2025 तक देश में ऑफिस स्पेस में 8.6 प्रतिशत सालाना की औसत दर से वृद्धि हुई है. सबसे तेज विकास बंगलुरु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में देखा गया है.

# मछुआरों के जीवन में तकनीकी दस्तक

तीन नवंबर से शुरू होगा राष्ट्रीय सर्वेक्षण अभियान

व्यास-भारत और व्यास-सूत्र ऐप लॉन्च

कोच्चि, 31 अक्टूबर. देश के समुद्री मत्स्योद्योग क्षेत्र की दशा और दिशा तय करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार तीन नवंबर से पांचवीं राष्ट्रीय समुद्री मत्स्योद्योग जनगणना शुरू करने जा रही है. यह जनगणना 18 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें देश के तटीय इलाकों के 5,000 से अधिक गांवों और बस्तियों में रहने वाले 12 लाख से ज्यादा मछुआरा परिवारों की विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शुक्रवार को कोच्चि में इसके लिए विकसित दो डिजिटल मोबाइल ऐप—व्यास-भारत और व्यास-सूत्र—



## जनगणना की प्रक्रिया हुई डिजिटल

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि देशभर में समुद्र में मछली पकड़ने और उससे जुड़े कार्यों में लगे लोगों की पांचवीं राष्ट्रीय समुद्री मत्स्योद्योग जनगणना (2025) तीन नवंबर से आरंभ होगी. यह अभियान 18 दिसंबर तक चलेगा और इसके अंतर्गत 5,000 से अधिक तटीय गांवों व बस्तियों में 12 लाख से ज्यादा मछुआरा परिवारों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा. इस बार जनगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोच्चि में दो विशेष मोबाइल ऐप—व्यास-भारत और व्यास-सूत्र—का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह कदम राष्ट्रीय जनगणना प्रणाली में डिजिटल प्रौद्योगिकी के समावेश का ऐतिहासिक सूत्रपात है.

का शुभारंभ किया. इस पहल से मत्स्योद्योग क्षेत्र की सटीक और पारंपरिक कागजी सर्वेक्षण की जगह डिजिटल तकनीक अपनाकर पर उपलब्ध कराई जाएगी.



# एप्पल का तिमाही मुनाफा रिकॉर्ड 86 प्रतिशत बढ़ा

कंपनी का कुल मुनाफा 2,746.6 करोड़ डॉलर पहुंचा

आइफोन 16 सीरीज का राजस्व में सबसे बड़ा योगदान

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर. अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने जुलाई सितंबर तिमाही में 86 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की. कंपनी का कुल मुनाफा 2,746.6 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया.

सिडो टिम कुक ने बताया कि भारत में अब तक की सबसे अधिक तिमाही बिक्री हुई है, जबकि आईफोन 16 सीरीज ने राजस्व में सबसे बड़ा योगदान दिया. अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने जुलाई-सितंबर में शुद्ध लाभ में

भारत और संयुक्त अरब अमीरात में नये स्टोर खोलने का उल्लेख

टिम कुक ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात में कुछ समय में नये स्टोर खोलने का भी उल्लेख किया. तिमाही के दौरान आईफोन की बिक्री 49 अरब डॉलर पर रही जो सालाना आधार पर छह प्रतिशत अधिक है. इसमें आईफोन 16 सीरीज का सबसे अधिक योगदान रहा. एप्पल के मुख्य वित्तीय अधिकारी केवन पारेख ने बताया कि भारत में आईफोन की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गयी. वर्ल्ड पैनल के सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका, जापान, चीन के शहरी इलाकों, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में आईफोन सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल रहे. तिमाही के दौरान एप्पल की कुल बिक्री 10,246.6 करोड़ डॉलर रही.

# वीआईटी चेन्नई का 10वां सालाना टेकनो वीआईटी शुरू

10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स तीन-दिवसीय टेकनो वीआईटी 25 इवेंट में हिस्सा ले रहे

नई दिल्ली 31 अक्टूबर. टेकनो वीआईटी का 10वां सालाना एडिशन, एक ग्लोबल इवेंट जिसमें स्टूडेंट्स कई टेकनोकल इवेंट्स और कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं, शुक्रवार को चेन्नई में शुरू हुआ.

पूरे भारत और थाईलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, म्यांमार, ताइवान और उज्बेकिस्तान जैसे 10 विदेशी देशों के 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स तीन-दिवसीय टेकनो वीआईटी 25 इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं. चेन्नई में रॉयल थाई कॉन्सुलेट-जनरल के कॉन्सल-जनरल, रचा अरिबर्ग, चीफ गेस्ट थे और उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया. एजीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट,



प्रिंस जयकुमार डी, गेस्ट ऑफ ऑनर थे और वीआईटी के वाइस प्रेसिडेंट, डॉ. जी.वी. सेल्वम ने अध्यक्षता की. अपने शुरुआती भाषण में, मिस्टर अरिबर्ग ने कहा कि इंजीनियरिंग और साइंस के

क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को टेकनोलॉजी का इस्तेमाल बुजुर्गों और समाज की मदद करने और ऑर्गनाइज्ड फ्रंट में लड़ने में भी योगदान देने के लिए करना चाहिए.

अरिबर्ग ने कहा, पूरी दुनिया में डिजिटल डिवाइड की एक गंभीर समस्या है—युवाओं और बुजुर्गों के बीच ज्ञान का अंतर. बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताएं, नहीं तो वे पीछे रह जाएंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टेकनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने परिवारों और समाज के अन्य बुजुर्गों के साथ ज्यादा बार बातचीत करें ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके. अपने प्रेसिडेंशियल भाषण में, डॉ. जी.वी. सेल्वम ने कहा कि युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में हाल के डेवलपमेंट्स के कारण उच्च शिक्षा के लिए वहां जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 44 प्रतिशत की कमी आई है.

# भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय आयातकों द्वारा 17 भारतीय किसान सम्मानित

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर. राजधानी में दो दिवसीय भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 शुक्रवार को भारत मण्डप में शुरू हुआ.

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अन्य सरकारी एवं उद्योग-विशेष निकायों के संस्थागत सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक खरीदार, निर्यातकों, नीति निर्माता और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग भारत के चावल व्यापार और कृषि नवाचार के भविष्य पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच पर आए हैं.

इस कार्यक्रम की शुरुआत एक उद्घाटन समारोह से हुई जिसमें भारत की पहली कृत्रिम बुद्धि आधारित चावल छंटाई प्रणाली का शुभारंभ किया गया. उद्घाटन समारोह में वैश्विक चावल व्यापार में भारत को बढ़ती प्रमुखता में भारतीय किसानों के योगदान को मान्यता देते हुए अंतरराष्ट्रीय आयातकों द्वारा 17 भारतीय किसानों को सम्मानित किया गया. समारोह में चावल उत्पादन में दक्षता, सटीकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई उन्नत मशीनरी और प्रसंस्करण समाधानों का भी प्रदर्शन किया गया.

हैदराबाद. कांग्रेस हो या भाजपा या कोई और प्रादेशिक पार्टी आमतौर पर पार्टियां विधायकों या सांसदों को जिला अध्यक्ष आदि नहीं बनाती हैं. जिला कमिटियों में उनको पदाधिकारी भी कम ही बनाया जाता है. ज्यादा से ज्यादा नेताओं को एजस्ट करके ही

## कांग्रेस विधायक बनेंगे जिला अध्यक्ष

कांग्रेस पार्टी इस अघोषित नियम को बदलने जा रही है. बताया जा रहा है कि तेलंगाना में पार्टी के विधायकों को ही जिला कमेटियों को जिम्मेदारी दी जाएगी. उन्हीं को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा. पार्टी के अध्यक्ष महेश गौड़ा ने कहा है कि विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा.

पता नहीं महेश गौड़ा और राज्य के मुख्यमंत्री रेंवत रेड्डी ने इस मामले में पार्टी आलाकमान की मंजूरी ली है या नहीं लेकिन अगर ऐसा होता है तो जिला से लेकर प्रदेश संगठन तक मुख्यमंत्री रेंवत रेड्डी का वर्चस्व स्थापित होगा. वैसे ही वे अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं. ध्यान रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में संगठन सुजन अभियान चलाया है. उन्होंने कई जगह कहा कि जिला कमेटियों को मजबूत करना सबसे पहली जरूरत है. इसके लिए संगठन सुजन अभियान के तहत दूसरे राज्यों के नेता जिलों में सर्वे करते हैं और पार्टी पदाधिकारियों से बात करके जिला अध्यक्ष के लिए नए नाम सुझाते हैं.

# लेंसकार्ट ने जुटाए 3,268 करोड़ रुपये

घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशक भी शामिल

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर. आईवियर आउटलेट की सीरीज चलाने वाली कंपनी लेंसकार्ट ने शुक्रवार को प्रारंभिक सार्वजनिक निगम खुलने से पहले बड़े निवेशकों को इकट्ठी जारी कर 3,268.36 करोड़ रुपये जुटाये हैं.

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड ने गुरुवार को शेयर बाजार को बताया कि 147 बड़े निवेशकों को 8,13,02,412 इकट्ठी शेयर के बदले उसने यह राशि जुटायी है. दो रुपये अंकित मूल्य वाले ये शेयर 402 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जारी किये गये. इन बड़े निवेशकों में घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशक भी शामिल हैं. कंपनी का आईपीओ आज खुला है और मंगलवार चार नवंबर तक जारी रहेगा. आईपीओ के तहत

9,97,61,257 शेयर बिक्री के लिए रखे गये हैं. कंपनी ने प्रति शेयर 382 रुपये से 402 रुपये का मूल्य दायरा तय किया है. कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्से के तहत प्रति शेयर 19 रुपये की छूट मिलेगी.

## पश्चिम मध्य रेल

No.C/BPL/e-auction/Oct/2025 Date 28-10-25 भोपाल मण्डल के पारसल लीज के अनुबंध के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की गई है। कैंटलीन पहले ही IREPS वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। विवरण प्रमाणनसार है: Catalogue number: C-BPL-SLR-OCT. Type of contract: Leasing, Lot no : 22169-SLR-F1-RKMP-SRC-25-1 (Parcel-SLR), 18235-SLR-R1-BPL-BSP-25-3 (Parcel-SLR), 12197-SLR-F1-BPL-GWL-25-3 (Parcel-SLR), 22165-SLR-R1-BPL-SGRL-25-3 (Parcel-SLR), 12197-SLR-R1-BPL-GWL-25-1 (Parcel-SLR), 14814-SLR-R1-BPL-JU-25-2 (Parcel-SLR), 18235-SLR-F2-BPL-BSP-25-1 (Parcel-SLR), 12854-SLR-R1-BPL-DURG-25-1 (Parcel-SLR), 22145-SLR-F1-BPL-REWA-25-1 (Parcel-SLR), 13026-SLR-R1-BPL-HWH-25-1 (Parcel-SLR), 12154-SLR-F1-RKMP-LTT-25-3 (Parcel-SLR), 12155-SLR-F1-RKMP-NZM-25-3 (Parcel-SLR), 11271-SLR-R1-ET-BPL-25-1 (Parcel-SLR), 11271-SLR-F1-ET-BPL-25-2 (Parcel-SLR), 22145-SLR-F2-BPL-REWA-25-1 (Parcel-SLR), 12183-SLR-F1-BPL-MBDP-25-3 (Parcel-SLR), 12185-SLR-F1-RKMP-REWA-25-3 (Parcel-SLR), 12001-SLR-F1-RKMP-NDLS-25-3 (Parcel-SLR), 19712-SLR-F1-BPL-JU-25-2 (Parcel-SLR). All Lot Contract Period: 3 Years. Date and time of start of e-auction for all lots: 10.11.2025 at 12:00 Hrs. प्रतिभागी ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन बidding कर सकते हैं। साइट: www.ireps.gov.in पर जाकर ई-नीलामी की मानक शर्तों और लॉट की विशेष शर्तों के विवरण के लिए जा सकते हैं। सहायक वाणिज्य प्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल

# स्थानीय निकायों को भी रेरा के दायरे में लाया जाये: आनंद

रेरा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अध्यक्ष आनंद कुमार ने रेरा को ज्यादा शक्तियां देने की बात कही

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अध्यक्ष आनंद कुमार ने रेरा को ज्यादा शक्तियां देने की वकालत करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसके पास स्थानीय निकायों को भी निर्देश देने का अधिकार होना चाहिए.

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा भारतीय रियल एस्टेट के विकास पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रेरा बनने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसमें अब भी कुछ कमियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, रेरा के पास सिर्फ आवास खरीदने वाले को, रियल एस्टेट एजेंट को और डेवलपर को निर्देश देने का अधिकार है. यदि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) निर्माण पूरा होने का प्रमाणपत्र (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) देने में देरी करता है, तो उसे निर्देश देने का अधिकार रेरा के पास क्यों नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि एमसीडी जैसे स्थानीय निकाय रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित मामलों में पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का हिस्सा हैं और उन्हें उचित निर्देश

देने का अधिकार रेरा के पास होना चाहिए. कुमार ने एक अन्य सुधार की सलाह देते हुए कहा कि बिक्री समझौतों को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने सलाह दी कि सभी बिक्री समझौते रेरा को सौंप दिये जाने चाहिए. रेरा उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, जिससे कोई भी उसे देख

सकता है. रियल एस्टेट सेक्टर के सभी पक्षों से ईमानदारी बरतने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आ रही समस्याओं की मुख्य वजह लालच है. खरीदार सस्ते मकान के लिए पूरी पड़ताल किये बिना अपनी मेहनत को कोई रियल एस्टेट एजेंट को सौंप देते हैं. रियल एस्टेट एजेंट लालच के कारण गलत दस्तावेज डेवलपर को देते हैं और डेवलपर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए गलत वादा करते हैं. उन्होंने खरीदारों से बिना पूरी पड़ताल किये पैसे न देने की अपील की. कुमार ने कहा कि रेरा कानून बनने से पहले रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसे की कमी थी और क्षेत्र मंदी से गुजर रहा था.



# तेजस्वी 'जननायक' नहीं?

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में अंदरूनी घमसान तेज हो गया है. ताजा विवाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 'जननायक' बताने को लेकर छिड़ा है. महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के कुछ हॉटिंग लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें जननायक के रूप में पेश किया गया. लेकिन यह उपाधि पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आ रही है, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव को अभी जननायक बनने में समय लगेगा. सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव की विरासत हैं.

मुख्य कार्यालय, विरार विरार (प) ता. वसई, जि. पालघर-४०१ ३०३

दुरध्वनी क्र. : ०२५०-२५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६ फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७ ई-मेल : vasavirarcorporation@yahoo.com जावक म.प्र. सूचित करता है कि मे : व.वि.श.म.प.क.व्य./१६६१/२०२५ दिनांक- ३१/१०/२०२५

# VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION NOTICE INVITING BID

Tenders is invited ONLINE from experienced Agencies for the following works on behalf of the COMMISSIONER, VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION (VVMCM), VIRAR. The tender document consisting of detailed scope of work, eligibility criteria, bid formats and important dates shall be uploaded on the website https://mahatenders.gov.in.

Sl.No.	Name of Work
1.	Selection of Agency for Cleaning of Drains/Chambers/Septic tank through Mechanised System along with collection, transportation and treatment of Faecal Sludge/septage/silt for Vasai-Virar City Municipal Corporation (VVMCM) on Public Private Partnership basis

Tender booklets will be available on e-tendering computer system at https://mahatenders.gov.in from date 01/11/2025. The tender is to be submitted online at https://mahatenders.gov.in For any technical difficulties in the e-tendering process, please contact the VVMCM's Solid Waste Management Department or Email at aarogheadoffice@gmail.com

Sd/- Dy. Municipal Commissioner, SWM Department, Vasai Virar City Municipal Corporation

# विशेष 38 साल तक रहा एक ही परिवार का राज

# क्या घोसी पर ऋतुराज कर लेंगे कब्जा

जहानाबाद. बिहार की राजनीतिक जमीन हमेशा से ही बड़ी उथल-पुथल रही है. जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट इसी राजनीति का एक शानदार मंच है. ये क्षेत्र भौगोलिक और सामाजिक रूप से थले ही पूरी तरह से ग्रामीण है, लेकिन यहां की चुनावी लड़ाइयां अक्सर राज्य की सुर्खियों में रही हैं.

घोसी विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है. घोसी का इतिहास 1977 से 2015 तक एक

## बिहार विधानसभा चुनाव, 2025



परिवार के इर्द-गिर्द घूमता रहा है. ये कहानी शुरू होती है जगदीश शर्मा से, जिन्होंने घोसी की राजनीति पर लगभग चार दशक तक अपना एकाधिकार बनाए

रखा. 1977 से 2009 तक जगदीश शर्मा लगातार आठ बार विधायक चुने गए. ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है कि इस दौरान उन्होंने कई पार्टियों की

सीढ़ियां चढ़ीं. जनता पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और जदयू के साथ-साथ दो बार निर्दलीय भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. जगदीश शर्मा सांसद बने पत्नी बन गई विधायक— जब जगदीश शर्मा 2009 में जहानाबाद से लोकसभा सांसद चुने गए, तो ये सीट उनके परिवार की विरासत बन गई. विधानसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी शांति शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुईं और 2010 के अगले विधानसभा चुनाव में उनके बेटे राहुल शर्मा ने जदयू के टिकट पर जीत दर्ज की.

# कार्यालय नगर पालिका परिषद डोंगर परासिया जिला सिन्दवाड़ा

Telephone: 07161.230508; E-mail: cmodongarparasiya@mpurban.gov.in क्रमांक 1200/PWD/NPP/2025 // निविदा सूचना // निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदाओं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समाप्ति पूर्व लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
2025_UAD_459657_1 दि. 30-10-2025	मुख्यमंत्री शहरी अधीसंरचना विकास योजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत शेष कार्यो के स्थान पर पृथक निर्माण कार्य	09 माह, 1,79,82,753/-	12,500/- 90,000/-	04-12-2025

शर्तें- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://www.mptenders.gov.in की वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

विनोद मालवीय अध्यक्ष नगरपालिका परिषद डोंगर परासिया, जि. सिंदवाड़ा ( म.प्र. ) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद डोंगर परासिया